



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

म. 234] नई विल्ली, सोमवार, मई 9, 1994/वैशाख 19, 1916

No. 234] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 1994/VAISAKHA 19, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

ग्रन्थिगृहना सं. 40/(ग्राह ई)/92-97

नई दिल्ली, 9 मई, 1994

विषय: नियोन आयात नीति 1992-97 के वैरा 121(घ) के प्रत्यर्गत भ्रमिगृहीत नियोन लाभों के लिए अन्तर्वर्ती अवस्था।

का.ग्रा. 365(य).—नियोन आयात नीति 1992-97 के पूर्व संशोधित संस्करण (मार्च, 1993) के वैरा 121(घ) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो 1992-97 की उक्त नीति के संशोधित संस्करण (मार्च, 1991) में से इदा दिया गया है।

2 पहले से की गई संविदाओं के लिए अन्तर्वर्ती प्रावधानों के लिए विभिन्न खेत्रों से अस्थायेन प्राप्त हुए हैं। दी गई भूमिका और संविदाओं की वृहद् प्रकृति और छूकि वास्तव

में तेज उत्पादन राष्ट्रीय प्राथमिकता है निम्नलिखित अन्तर्वर्ती व्यवस्था अधिसूचित की जाती है:—

**अन्तर्वर्ती व्यवस्थाएं :**

- (1) उन सभी भागों में जहाँ ओ.एल जी सी/ओ.आईएल/जी ए आई एल द्वारा 29 मार्च, 1994 को या इससे पहले आशय पत्र (एल ओ धाई) जारी किये गये हैं वे पूर्व संशोधित (मार्च, 1993) नीति के पैरा 121(घ) और 122 में प्रतिपादित अभिगृहीत नियति भागों के लिए पात्र होंगे,
- (2) संविवाहों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा लेकिन ओ.एन जी सी/ओ.आईएल/जी ए आई एल प्रत्येक भागों में यह प्रमाणित करेगी कि आशय पत्र 29 मार्च, 1994 को या इससे पहले जारी किया गया था,
- (3) जिन भागों में आशय पत्र 29-3-94 को या इससे पहले जारी किये गये हैं के संबंधी लाइसेंस हेतु आवेदन महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय के संबंधित कार्यालय में 30-11-94 या इससे पहले दर्ज करा लिये जायें। शुल्क वापसी और टर्मिनस उत्पाद शुल्क की वापसी के अन्य भागों के लिये 29 मार्च, 1994 को लागू नीति की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दावा कियाजा सकता है, और
- (4) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभिगृहीत नियति नीति के अन्तर्गत लाभ तक तक की उपलब्ध होंगे जब तक आपूर्तियां मूल रूप से निर्धारित डिलीवरी के लिए गई गई संविदा की सारी तक प्रभावित होती हो न कि उसके बाद किसी बढ़ाई गई अवधि के लिए।

3. उपर्युक्त अन्तर्वर्ती व्यवस्था एकिजम नीति 1992-97 के पैरा 56 (4) के पूर्व संशोधित संस्करण (मार्च, 1993) में यथा उपलब्ध शुल्क मुक्त योजना (अध्याय-7) के अन्तर्गत विशेष ग्रामदाय लाइसेंसों पर विचार करने या जारी करने हेतु भी लागू होगी।

4. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के लिये आदेश केन्द्रीय सरकार के विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) के धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रक्रियों का प्रयोग करते हुए दिया जाता है।

5. उसे सार्वजनिक शृंति में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 3/15/94-आईसी-2]

दा.पी.एल. संजीव रेडी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**NOTIFICATION NO. 40|(RE)|92—97**

New Delhi, the 9th May, 1994

**Subject.—Transitional arrangements for deemed export benefits under para 121(d) of Export & Import Policy, 1992—97,**

**S.O. 365(E).—Attention is invited to para 121(d) of the pre-revised Edition (March 1993) of the Export & Import Policy, 1992—97 which stands deleted in the Revised Edition (March 1994) of the said Policy, 1992—97.**

2. Representations have been received from various quarters requesting for transitional provisions for contracts already entered into. Given the background and the bulk nature of the contracts and in fact that Oil Production is a National priority, the following transitional arrangement is notified :

**Transitional arrangements**

- (i) All cases where letters of intent (LOI) have been issued by ONGC|OIL|GAIL on or before 29th March, 1994 would be entitled to the deemed export benefits as enunciated in the pre-Revised (March, 1993) Policy under para 121(d) and 122 thereof;
- (ii) Registration of contracts will not be necessary, but ONGC|OIL|GAIL will certify in each case that the letter of intent was issued on or before 29th March, 1994;
- (iii) Applications for licences in respect of cases where LOIs have been issued on or before 29-3-94 will be filed with the concerned office of the DGPT on or before 30-11-94. The other benefits of duty drawback and refund of terminal excise duty may be claimed as per the normal procedures of the policy existing as on 29th March, 1994; and
- (iv) The benefits under the deemed export policy, as stated above, would be available only so long as supplies have been effected by the contracted date of delivery stipulated originally and not for any extensions thereafter.

3. The above transitional arrangements will also be applicable for consideration or issue of Special Imprest Licences under Duty Exemption Scheme (Chapter VII) as available in the pre-revised Edition (March, 1993) of Exim Policy 1992—97 in para 56(iv) thereof.

4. The above arrangements are ordered by the Central Government in exercise of the powers conferred under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

5. This issues in public interest.

[File No. 3/15/94 IPC-II]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade.